NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय

(Introduction to International Relations)

B.P.S.C.-134

B.A. General - 4th Semester

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Ved Prakash Sharma*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय

(Introduction to International Relations)

Question Paper—June-2023 (Solved) 1

Question Paper—December-2022 (Solved) 1-2

Question Paper–Exam Held in March-2022 (Solved) 1-3

Sample Question Paper–1 (Solved) 1

Sample Question Paper–2 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

खंड-1 : परिचय (Introduction)

1. अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ 1
(Understanding International Relations)

2. मूलभूत संकल्पनाएँ : राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के तत्त्व 13
(Basic Concepts : Elements of National Power, National Interest, Collective Security, Balance of Power)

3. वैश्विक व्यवस्था का विकास (विश्वयुद्ध II तक) 27
(Evolution of International System – Up to the World War-II)

खंड-2 : दृष्टिकोण (Approaches)

4. यथार्थवाद 35
(Realism)

5. सिस्टम (व्यवस्था) उपागम 45
(Systems Approach)

6. निर्भरता सिद्धांत 54
(Dependency Theory)

7. रचनावाद 63
(Constructivism)

खंड-3 : अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की घटनाएँ (State and District Adminstration)

8. शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके चरण 70
(Origins and Phases of the Cold War)

9. शीत युद्ध का अंत और इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव 82
(End of the Cold War and its impact on International Relations)

10. शक्ति के उभरते केन्द्र 92
(Emergings Centres of Power)

11. वैश्वीकरण 102
(Globalisation)

खंड-4 : अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organisations)

12. संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और कार्य 113
(Role of Functions of United Nations)

13. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन 122
(International Economic Organisations)

14. क्षेत्रवाद और नव-क्षेत्रवाद 136
(Regionalism and New Regionalism)

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय

(Introduction to International Relations)

B.P.S.C.-134

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक* ***समान*** *हैं।*

खण्ड-I

प्रश्न 1. राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा और इसके तत्वों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-13, 'राष्ट्रीय शक्ति का विचार'

प्रश्न 2. सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-21, प्रश्न-4

प्रश्न 3. नव-यथार्थवाद के प्रमुख तर्कों की विवेचना कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-38, प्रश्न-3

प्रश्न 4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) कठोर और नरम शक्ति (Hard and soft power)

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-92, 'शक्ति के प्रकार : कठोर और नरम'

(ख) सामाजिक रचनावाद

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-3, 'सामाजिक रचनावाद'

खण्ड-II

प्रश्न 5. गोर्बाचोव की ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका नीतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-85, प्रश्न-1

प्रश्न 6. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-7, प्रश्न-1

प्रश्न 7. शीत युद्ध के पश्चात् की अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-85, प्रश्न-2

प्रश्न 8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.)

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-122, 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष'

(ख) सांस्कृतिक वैश्वीकरण

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-104, 'सांस्कृतिक वैश्वीकरण'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

December – 2022

(Solved)

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय

(Introduction to International Relations)

B.P.S.C.-134

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक* ***समान*** *हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'उदारवाद', पृष्ठ-4, प्रश्न 2

प्रश्न 2. कैनेथ वाल्ट का सिस्टम सिद्धांत (विधि) की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-46, 'कैनेथ वाल्ट्ज का सिस्टम उपागम'

प्रश्न 3. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत का उल्लेख कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-5, प्रश्न 3

प्रश्न 4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) हेलसिंकी समझौता

उत्तर–हेलसिंकी घोषणा एक ऐसा अधिनियम था, जिसका उद्देश्य सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच तनाव कम करने की भावना को पुनर्जीवित करना था। 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, नाटो के सभी सदस्यों और वारसॉ संधि ने हेलसिंकी, (फिनलैंड) में आयोजित यूरोप (CSCE) में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन की बैठक के दौरान एक समझौता किया और हेलसिंकी अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। डेंटेंट अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राज्य सचिव हेनरी किसिंजर द्वारा तैयार की गई नीति थी। तनावमुक्ति के तहत कुछ महत्त्वपूर्ण लाभ हुए, क्योंकि कई विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) और हथियारों को कम करने के समझौतों पर शीत युद्ध के दो विरोधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमों में निक्सन की मास्को की ऐतिहासिक यात्रा भी शामिल है। 1975 के मध्य तक डेंटेंट की भावना बहुत कम थी। निक्सन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और अमेरिका वियतनाम से हट गया था, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण वियतनाम पर कम्युनिस्ट उत्तर की जीत हुई थी। सोवियत संघ के साथ शस्त्र कटौती वार्ता की प्रगति में ठहराव था। जुलाई 1975 में, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हेलसिंकी में सीएससीई को बुलाकर तनावमुक्ति की नीति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। 1 अगस्त को उपस्थित लोगों ने हेलसिंकी फाइनल एक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस अधिनियम ने सीएससीई को एक सतत सलाहकार संगठन के रूप में गठित किया और भविष्य की चर्चा के लिए कई मुद्दों को निर्धारित किया। आर्थिक और व्यापार के मुद्दे, हथियारों की कमी और मानवाधिकारों की सुरक्षा इसके एक हिस्से थे। हेलसिंकी समझौते औपचारिक लेकिन गैर-बाध्यकारी समझौतों की एक शृंखला है, जिन पर अगस्त 1975 में हस्ताक्षर किए गए थे।

हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 35 देशों ने निम्नलिखित सिद्धांतों को स्वीकार किया–

शीत युद्ध/89 की उत्पत्ति और चरण

- संप्रभु समानता और संप्रभुता में निहित अधिकारों के लिए सम्मान।

बल प्रयोग की धमकी या प्रयोग से बचना।

- सरहदों की अनुल्लंघनीयता।
- राज्यों की प्रादेशिक अखंडता।
- विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
- आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप।
- विचार की स्वतंत्रता सहित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान,
- विवेक, धर्म या विश्वास, लोगों के समान अधिकार और आत्मनिर्णय, के तहत दायित्वों की सद्भावना में पूर्ति,
- राज्यों के बीच सहयोग।

शीत युद्ध के तनाव को कम करने की दिशा में हेलसिंकी समझौते को एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया था लेकिन हेलसिंकी की भावना कमजोर थी और तनावमुक्ति का पुनरुद्धार बहुत जीवित साबित हुआ।

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय
(Introduction to International Relations)

खंड-1 : परिचय
(Introduction)

अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ
(Understanding International Relations)

1

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय संबंध से तात्पर्य दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों के स्वरूप से है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक संबंध स्थापित होते हैं। साथ-ही-साथ संप्रभु राज्यों, अंतरसरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका का भी अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक व्यापार प्रतिरूप एवं नेतृत्व क्षमता भी प्रभावित करती है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं संपन्नता को सुनिश्चित करने के लिए न सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ बल्कि अन्य राष्ट्रों के साथ भी सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध सहायक सिद्ध होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझना विश्व व्यवस्था के अनेक दृष्टिकोणों की तलाश और पेशकश करने में सहायता करता है। 1930 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ यथार्थवाद और उदारवाद की मुख्यधारा और सशक्त हुई है। इन दो दृष्टिकोणों को परंपरागत रूप से कूटनीतिक, सैन्य और रणनीतिक शक्तियों और उन्हें विस्तार देने के तरीकों के रूप में माना गया था। 1960 के दशक में व्यवहारवादियों और परंपरावादियों के मध्य बहस हुई, शक्तियों का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझाने की कसौटी मानते हैं। 1970 और 1980 के दशक में तीसरी बहस उदारवादियों तथा यथार्थवादियों एवं मार्क्सवादियों के बीच थी। मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आर्थिक दृष्टि से समझते थे।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसा वैचारिक ढांचा तैयार करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सके। इस अध्याय के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण, एक उपागम के रूप में उदारवाद, आलोचनात्मक उपागम तथा इन विविध सैद्धांतिक और अवधारणाओं की आलोचना आदि का अध्ययन करेंगे।

अध्याय का विहंगावलोकन

यथार्थवाद

यथार्थवाद अथवा राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण की शुरुआत के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत रहा है। यह सिद्धांत उन प्राचीन परंपरागत दृष्टिकोणों पर भरोसा करने का दावा करता है, जिसमें थ्यूसाइड्स, मैकियावेली और हॉब्स जैसे लेखक शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पारंपरिक दृष्टिकोण की प्रमुख प्रणालियां हैं–यथार्थवाद, आदर्शवाद तथा नवयथार्थवाद। यथार्थवादियों का मत है कि सत्ता के लिए संघर्ष ही समस्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केन्द्रीय तत्त्व है। उनका यह मानना है कि राष्ट्रों के मध्य वैमनस्य और द्वंद्व, किसी-न-किसी रूप में सदैव मौजूद रहते हैं, जिस प्रकार निजी हित वैयक्तिक आचरण को संचालित करता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय हित राष्ट्र-राज्यों की विदेश नीति को संचालित करता है। निरंतर द्वंद्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है और यही द्वंद्व सीधा सत्ता-संघर्ष का परिणाम है। यथार्थवादियों के लिए राष्ट्रीय हित ही एकमात्र लक्ष्य है, जिसे वे हर कीमत पर बढ़ावा देना चाहते हैं। अतः यथार्थवादियों के लिए राष्ट्रों के मध्य सत्ता वितरण की व्याख्या करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एकमात्र काम है।

हंस मोरगेंथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद के छह सिद्धांतों को उजागर किया है, जो यह बताते हैं कि राज्य कैसे काम करता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं–

1. राजनीति उद्देश्य कानूनों द्वारा शासित होती है, जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में निहित होती हैं।
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हित की अवधारणा की दृष्टि से परिभाषित किया जा सकता है।

www.neerajbooks.com

3. राज्य शक्ति के प्रकार और प्रकृति समय, स्थान और संदर्भ में अलग होंगे, परंतु हित की संकल्पना सुसंगत रहती है।
4. सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत राज्य के व्यवहार का मार्गदर्शन नहीं करते हैं।
5. यथार्थवाद के अनुसार सभी चर एवं अचर वस्तुएं एक अवयव के रूप हैं, जिसमें निरंतर प्रक्रिया हो रही है।
6. इसका राजनीतिक क्षेत्र स्वायत्त है अर्थात् यह नीति किसी राष्ट्र की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है?

नव-यथार्थवाद

नव-यथार्थवाद केनेथ वाल्ट्ज द्वारा अपनी पुस्तक 'थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स' में इसे यथार्थवाद के ही उन्नत विकास के रूप में प्रस्तुत किया था। वाल्ट्ज के नव-यथार्थवाद का मानना है कि संरचना के प्रभाव को राज्य के व्यवहार को समझाने के रूप में लिया जाना चाहिए। संरचना को दो रूपों में परिभाषित किया गया है, प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का सिद्धांत, जो कि अराजकता लिए हुए है और द्वितीय, इकाइयों में क्षमता का वितरण।

संरचना एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मौजूदा अराजक व्यवस्था में हम पाते हैं कि एक शक्तिशाली राष्ट्र की रुचि दूसरे राष्ट्रों को अपेक्षित सामर्थ्य प्राप्त करने से रोकने में होती है।

इनका यह भी मानना है कि राष्ट्र-राज्य आज भी अंतर्राष्ट्रीय समिति में मुख्य भूमिका निभाते हैं तथा इनका यह विचार है कि आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पहचान अराजकता व बहुकेन्द्रक गतिविधियों के रूप में की जा सकती है तथा इन गतिविधियों का स्रोत अब मात्र राज्य ही नहीं, अपितु गैर-राज्य तत्त्व भी है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक युद्ध, गृहयुद्ध की बढ़ती घटनाएं और प्रतियोगी बहुराष्ट्रीय निगमों के कारण यह जटिलता और भी जटिलतर हो गई है।

अत: नव-यथार्थवाद इस अराजक विश्व में सत्ता-संघर्ष के तत्त्व पर विशेष बल देता है। सत्ता-संघर्ष केवल राज्यों के बीच ही नहीं, अपितु उनमें से प्रत्येक के अन्दर भी है।

उदारवाद

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उदारवादी सिद्धांतों का अग्रदूत आदर्शवाद था। आदर्शवाद जो स्वयं को यथार्थवादियों की आलोचना के रूप में देखता था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद एक वैचारिक दृष्टिकोण है, जो यह मानता है कि एक राज्य को अपनी विदेश नीति का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसे अपने आंतरिक राजनीतिक दर्शन में अपनाना चाहिए। विल्सन का आदर्शवाद उदार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के लिए एक अग्रदूत के रूप में था, जो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संस्था निर्माताओं के बीच पैदा हुआ।

उदारवाद यह मानता है कि राज्य की क्षमताओं के बजाय राज्य की प्राथमिकताएं, राज्य के व्यवहार के लिए मुख्य निर्धारक होती हैं। यथार्थवाद के विपरीत, जहां राज्य एक एकात्मक अभिनेता के रूप में देखा जाता है, वहीं उदारवाद राज्य के कार्यों में बहुलता के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। इस प्रकार प्राथमिकताएं अलग-अलग राज्यों में उनकी संस्कृति, आर्थिक प्रणाली या सरकार के प्रकार के रूप में अलग-अलग कारकों पर निर्भर करेंगी। उदारवादी यह भी मानते हैं कि राज्यों के बीच संपर्क केवल राजनीतिक अथवा सुरक्षा के मामलों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इनमें आर्थिक अथवा सांस्कृतिक मामलों के लिए भी आपस में संपर्क होता रहता है, चाहे वह वाणिज्यिक कम्पनियों, संगठनों या व्यक्तियों के माध्यम से ही हो। इस प्रकार एक अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बावजूद सहयोग और सत्ता के व्यापक विचार के लिए बहुत से अवसर विद्यमान हैं।

1970 के दशक के बाद उदारवाद को नवउदारवाद के तहत पुनर्जीवित किया गया था। उदारवाद के अंदर प्रमुख विषय हैं– (1) अन्योन्याश्रय उदारवाद, (2) लोकतांत्रिक उदारवाद तथा (3) उदार संस्थावाद।

आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य

1980 के दशक में आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बल मिला। उन्होंने एक उत्तर-वस्तुनिष्ठवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया, जो सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ता है। आलोचनात्मक सिद्धांत अनुकरणीय सिद्धांत है तथा वे उपेक्षित समूहों के उत्पीड़न को स्वतंत्रता की दिशा में काम करते हैं। प्रमुख आलोचनात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं–

मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद और आलोचनात्मक सिद्धांत

मार्क्सवाद और नव-मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के संरचनावादी मानदण्ड हैं, जो यथार्थवादी और उदारवादियों के राज्य संघर्ष अथवा सहयोग के दृश्य को अस्वीकार करते हैं और इनके बजाय ये आर्थिक और भौतिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अस्थिरता का प्रमुख स्रोत पूंजीवादी वैश्वीकरण होगा, विशेष रूप से दो वर्गों के बीच संघर्ष, राष्ट्रीय पूंजीपति और महानगरीय सर्वहारा वर्ग। ऐतिहासिक भौतिकवाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामलों में प्रक्रियाओं को समझने के लिए मार्क्सवाद की मार्गदर्शिका बने जा रहा था। इस प्रकार मार्क्स के लिए मानव इतिहास भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने और वर्ग संघर्ष और उस पर आधारित शोषण का विरोध करने के लिए एक संघर्ष रहा है। इसकी वैचारिक आलोचना के बावजूद मार्क्सवाद के पक्ष में मजबूत पक्ष और फायदे हैं। सर्वप्रथम इसका अन्याय और असमानता पर बल देना हर काल के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि मानव समाज की दो विफलताएं कभी अनुपस्थित नहीं रहेंगी। नव-यथार्थवाद की भांति मार्क्सवादी भी एक संरचनात्मक सिद्धांत है, लेकिन यह सैन्य-राजनीतिक ढांचे के बजाय आर्थिक

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

क्षेत्र पर केन्द्रित है। इसका विश्लेषण आधार और अधिरचना के बीच के संबंध को बताता है। संरचनात्मक प्रभावों का स्रोत अराजकता नहीं, अपितु उत्पादन का पूंजीवादी तरीका है, जो अन्यायपूर्ण राजनीतिक संस्थानों और राज्य संबंधों को परिभाषित करता है।

इस आर्थिक कमी को इस सिद्धांत का प्रमुख दोष भी माना जाता है। नव-ग्रामशीवादी स्कूल ने इसके समाधान में, एक और प्रस्ताव दिया। वैश्विक पूंजीवाद, राज्य संरचना और राजनीतिक-आर्थिक संस्थानों को मिलाकर, यह वैचारिक वर्चस्व का एक सिद्धांत बनाने में सफल रहा। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में और बाहर सशक्त कुलीनों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से आधिपत्य स्थापित किया जाता है।

कालानुक्रमिक दृष्टिकोण से मार्क्सवाद ने समालोचनात्मक सिद्धांत के लिए नींव तैयार की और यह एंग्लो-अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख दृष्टिकोणों की समस्याएं सुलझाने में बेहतर साबित हुआ है। मार्क्सवाद का मानक नुकसान यह है कि यूरोपीय ज्ञानोदय के ब्रह्मांडवाद मूल्य से प्रेरित होने के कारण इसे यूरोकेन्द्रीय रूप में देखा जा सकता है।

निर्भरता सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है, जो यह तर्क देता है कि शक्ति की खोज में विकसित देश, राजनीतिक सलाहकारों, मिशनरियों, विशेषज्ञों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से विकासशील देशों में उपयुक्त प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था में उन्हीं एकीकृत करते हैं। इससे एक आर्थिक पैटर्न प्रकट होता है, जहां विकासशील देश कच्चा माल निर्यात करके संसाधित माल आयात करते हैं, जिससे वे विकसित देशों पर निर्भर हो जाते हैं।

यथार्थवादी और उदारवादी दोनों ही इस सिद्धांत को राजनीति से प्रेरित मानते हैं और कहते हैं कि इसका दृष्टिकोण उद्देश्यपूर्ण और पक्षपाती है। उत्तर-प्रत्यक्षवादी इस मान्यता से असहमत हैं कि वर्ग संघर्ष मानव जीवन का सबसे प्रमुख भाग है, जिसके आधार पर संपूर्ण मानव इतिहास और व्यवहार समझा जा सकता है।

नारीवाद

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी दृष्टिकोण 1960 के दशक में यूरोप में प्रकट हुआ, जहां महिलाओं ने विचार प्रकट किया कि वे जीव विज्ञान में अंतर के कारण अधीनस्थ हैं। उन्होंने महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिका को चुनौती दी और इस बात पर बल दिया कि ये भूमिकाएं स्वाभाविक नहीं हैं। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि महिलाओं के अनुभवों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से बाहर रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादियों का मानना है कि लिंग संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अभिन्न अंग हैं। अत: राजनयिक महिलाओं और वैवाहिक संबंधों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

नारीवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जेंडर विवेक शून्य होने का आरोप लगाया। यह महिलाओं की आवाज और विचारों को शामिल नहीं करता। राज्य की नीति निर्यात आय, आर्थिक विषयों और तुलनात्मक श्रम लागत के घटकों पर संचालित होती है, परंतु राज्य ने सामाजिक सेवाओं के वितरण, पूर्ण रोजगार के प्रावधान, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक असमानताओं को दूर करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है।

नारीवाद के अंदर कई तत्व हैं, जो महिलाओं को अपने अंतर को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदार नारीवादी समान राजनीतिक अधिकारों और सार्वजनिक क्षेत्र में समानता पर बल देते हैं, जबकि समाजवादी नारीवादी सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने और महिलाओं की मुक्ति के बारे में बात करते हैं।

उत्तर-संरचनावाद

उत्तर-संरचनावाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे ज्यादातर दृष्टिकोण से अलग है, क्योंकि यह स्वयं को एक ऐसे सिद्धांत, स्कूल या प्रतिमान के रूप में नहीं देखता है, जो कि केवल किसी एक ही विषय के बारे में लेखा-जोखा रखता है। इसके बजाय उत्तर-संरचनावादी दृष्टिकोण एक लोकाचार, तरीका और दृष्टिकोण है, जो विशेष रूप से आलोचनाओं की जांच एवं खोज करता है। उत्तर-संरचनावाद आलोचना को एक स्वाभाविक सकारात्मक तरीके से देखता है, जो कि विकल्पों की खोज के लिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है।

हरित राजनीति

हरित राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों का एक उप-क्षेत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग से संबंधित है। 1970 के दशक के बाद से यह पर्यावरणीय नीतिगत चर्चा में पर्यावरण का एक प्रमुख कारक बन गया। 1990 के दशक में इसने जलवायु परिवर्तन की चिंता के साथ और ज्यादा संकर्षण हासिल किया। यह सिद्धांत मानव जाति और प्रकृति के मध्य एक कड़ी की व्याख्या करता है। हरित राजनीति सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की जरूरत पर बल देता है। इस सिद्धांत का मानना है कि उन्नति और विकास केवल तभी स्थिर रह सकता है, जब यह पर्यावरण के साथ मेल खाता हो।

सामाजिक रचनावाद

सामाजिक रचनावाद या रचनावाद नव उदारवादी तथा नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के प्रभुत्व के समक्ष एक चुनौती के रूप में वर्णित किया जाता है। माइकल बर्नेट वर्णन करते हैं कि रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों को इस रूप में समझा जाता है कि विचार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं। यह संरचना कैसे राज्यों के हितों तथा उनकी पहचान को परिभाषित करती है। राज्य और गैर-राज्य अभिनेता इस संरचना को कैसे पुन: प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक रचनावाद के प्रमुख सिद्धांत का यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रेरक विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान द्वारा निर्मित होती है। सामाजिक रचनावाद का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता सामाजिक रूप से ज्ञानात्मक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होती है। यह सिद्धांत

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों की वैज्ञानिक विधि और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के उत्पादन में सिद्धांतों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए एक बहस के रूप में प्रकट हुआ है।

उत्तर-उपनिवेशवाद

उत्तर-उपनिवेशवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण में मुख्यधारा का क्षेत्र नहीं माना जाता है। उत्तर-उपनिवेशवाद विश्व राजनीति में औपनिवेशिक स्थिरता की शक्ति और नस्लवाद के अस्तित्व को जारी रखने पर बल देता है।

उत्तर-उपनिवेशवाद का उदय 1919-1945 में माना जाता है, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् ही उच्च शिखर पर पहुँचा। उत्तर-उपनिवेशवाद यह विचार प्रकट करता है कि पाश्चात्य जगत किस प्रकार अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। वह बताता है कि 'श्वेत व्यक्ति का बोझ' सिद्धांत ढोंग है और यह अल्पविकसित और विकासशील देशों को पाश्चात्य प्रभुत्व का अधीनस्थ बनाए रखने का एक तरीका है।

उत्तर-उपनिवेशवाद के आलोचकों का मानना है कि पाश्चात्य विचारों को छोड़कर उत्तर-उपनिवेशवादियों ने परंपरागत मूल्यों और अधिकार संरचनाओं के स्थान पर प्रगतिशील राजनीति को छोड़ दिया है। नारीवादियों का मानना है कि पाश्चात्य विचारों को छोड़ना उनके आंदोलन की उन्नति में रुकावट है क्योंकि ज्यादातर स्वदेशी संस्कृति महिलाओं के अधिकारों को दबाती है।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. यथार्थवाद की अवधारणा को समझाइए।

उत्तर–यथार्थवाद के लिए अंग्रेजी का शब्द 'रियलिज्म' है। 'रियल' शब्द ग्रीक भाषा के रीस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वस्तु। अत: रियल का अर्थ होता है वस्तु संबंधी। यही कारण है कि यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व से संबंधित एक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु सत्य है और प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अनुभव हमें इन्द्रियों से होता है। वास्तव में यथार्थवाद एक भौतिकवादी दर्शन है। वस्तु को वास्तविक अथवा यथार्थ मानने के कारण ही इस विचारधारा को वास्तववाद या यथार्थवाद की संज्ञा दी गई है। यथार्थवाद संसार को मिथ्या कहने वाली भावना का विरोधी स्वर है।

यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण की शुरुआत के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत रहा है। यह सिद्धांत उन प्राचीन परंपरागत दृष्टिकोणों पर भरोसा करने का दावा करता है, जिसमें थ्यूसाइड्स, मैकियावेली और हॉब्स जैसे लेखक शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पारंपरिक दृष्टिकोण की प्रमुख प्रणालियां हैं–यथार्थवाद, आदर्शवाद तथा नवयथार्थवाद। यथार्थवादियों का मत है कि सत्ता के लिए संघर्ष ही समस्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केन्द्रीय तत्त्व है। उनका यह मानना है कि राष्ट्रों के मध्य वैमनस्य और द्वंद्व, किसी-न-किसी रूप में सदैव मौजूद रहते हैं, जिस प्रकार निजी हित वैयक्तिक आचरण को संचालित करता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय हित राष्ट्र-राज्यों की विदेश नीति को संचालित करता है। निरंतर द्वंद्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है और यही द्वंद्व सीधा सत्ता-संघर्ष का परिणाम है। यथार्थवादियों के लिए राष्ट्रीय हित ही एकमात्र लक्ष्य है, जिसे वे हर कीमत पर बढ़ावा देना चाहते हैं। अत: यथार्थवादियों के लिए राष्ट्रों के मध्य सत्ता वितरण की व्याख्या करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एकमात्र काम है।

यथार्थवादियों का मानना है कि राष्ट्र-राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिनेता होते हैं। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक राज्य केन्द्रित सिद्धांत है। यह विचार उदार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ विरोधाभास प्रकट करता है, जो गैर-राज्य अभिनेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में समायोजित करता है।

यथार्थवादियों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजकता के द्वारा संचालित है, जिसका अर्थ है कि वहां केन्द्रीय सत्ता नहीं है, जो राष्ट्र राज्यों में सामंजस्य रख सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वार्थी राज्यों के बीच सत्ता के लिए एक संघर्ष है। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य के अस्तित्व की गारंटी के लिए राज्यों की सहायता पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी चाहिए।

अत: यथार्थवाद में अनेक मान्यताएं हैं। यथार्थवादी मानते हैं कि राष्ट्र-राज्य इस अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ऐकिक व भौगोलिक आधारित हैं, जहां कोई भी वास्तविक आधिकारिक विश्व सरकार के रूप में मौजूद नहीं है, जो इन राष्ट्र-राज्यों के मध्य अन्त:क्रिया या सहभागिताओं को विनियमित करने में सक्षम हो। दूसरे, यह अंतरसरकारी संगठनों (IGOs), अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (IOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (MNCs) के बजाय संप्रभु राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्राथमिक अभिनेता मानते हैं। इस प्रकार राज्य ही सर्वोच्च व्यवस्था के रूप में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। ऐसे में एक राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने, अपनी स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और इन प्राथमिक उद्देश्यों के साथ अपने स्वयं के स्वार्थ की खोज में एक तर्कसंगत स्वायत्त अभिनेता के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की रक्षा करने का प्रयास करता है।

प्रश्न 2. उदारवाद क्या है? उदारवाद के प्रमुख विषयों की व्याख्या करें।

उत्तर–अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद वह विचारधारा है, जिसके तहत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम माना जाता है। स्वतंत्रता, सहयोग, समझौता, शांति और प्रगति इसके प्रमुख

www.neerajbooks.com